जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 144 प्रभात उदयपुर, शनिवार 29 मार्च, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

पहली बार चिदंबरम, कांग्रेस अधिवेशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं हैं

इसी प्रकार यह भी पहली बार हो रहा है कि अधिवेशन में केवल एक ही प्रस्ताव पेश किया जायेगा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 मार्च। कांग्रेस पार्टी अहमदाबाद में होने वाले अपने ए.आई.सी.सी. अधिवेशन की तैयारियों में जुटी है, ऐसे में यह पहली बार है जबकि, पी. चिदंबरम ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं हैं, जो कि- ए.आई.सी.सी. के सम्मुख पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को ड्राफ्ट करेगी।

और पहली बार ही ऐसा होगा कि ए.आई.सी.सी. अधिवेशन में सिर्फ एक ही प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

इससे पहले कांग्रेस में परंपरा रही है कि ए.आई.सी.सी. अधिवेशनों में राजनीतिक, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रीय अथवा अन्य किसी विषय पर अध्यक्ष की अनुमति लेकर लगभग आधा दर्जन प्रस्ताव पेश होते आए हैं।

यह भी चर्चा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, जबकि, अभी उनकी उतनी परिपक्वता, वरिष्ठता या बौद्धिक क्षमता नहीं है कि वे निर्णय ले सकें कि क्या-क्या मसले व मुद्दे प्रस्ताव में जरुर सम्मिलित होने चाहिए।

- जैसा कि विदित ही है, अहमदाबाद में कांग्रेस का 9 अप्रैल को एकदिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया है और उसमें एक ही प्रस्ताव पेश किया जायेगा। इससे पहले कांग्रेस में परम्परा रही है कि राजनीतिक, इकोनॉमिक, अंतरर्राष्ट्रीय व अन्य किसी विषय पर, अध्यक्ष की अनुमति लेकर, लगभग आधा दर्जन प्रस्ताव पेश होते आये हैं।
- इस बात की भी चर्चा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, जबकि उनकी अभी उतनी परिपक्वता, वरिष्ठता या बौद्धिक क्षमता नहीं है कि वे निर्णय ले सकें कि क्या-क्या मसले व मुद्दे प्रस्ताव में जरुर सम्मिलित होने चाहिये। पहली बैठक में चर्चा इस बात पर सीमित रही कि प्रस्ताव व पेपर की "थीम" क्या होनी चाहिये।
- संगठनात्मक पुनर्गठन पर राहुल गांधी की स्पष्ट सोच है कि पार्टी को सहयोगी दलों के दबाव में नहीं आना चाहिये और पार्टी का फोकस डी.सी.सी. को मजबूत करने पर रहना चाहिये।

आज दोपहर को हुई ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली मीटिंग में चर्चा इस बात पर सीमित रही कि प्रस्ताव व पेपर की थीम क्या होनी चाहिए।

वस्तुतः ए.आई.सी.सी. अधिवेशन केवल एक दिन का ही है तथा 9 अप्रैल को आयोजित होगा। आठ अप्रैल को तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) की मीटिंग होनी है।

राहुल गांधी की सोच के अनुसार, अधिवेशन में केन्द्रीय मुद्दे होंगे- भाजपा पर प्रहार, मोदी सरकार की अक्षमता, अर्थव्यवस्था में गिरावट तथा आम लोगों की कीमत पर बड़े कॉर्पोरेट घरानो को मनमानी की छूट देना। राहुल गांधी का मानना है कि संगठनात्मक मोर्चे पर, कांग्रेस को विभिन्न राज्यों में अपनी राजनैतिक संभावनाएं पुनः तलाशने एवं प्राप्त करने की जरूरत है तथा पार्टी को अपने मित्र दलों के दबाव के आगे समर्पण नहीं करना चाहिये। इसके अलावा, राहुल अपने इस निर्णय पर अटल हैं कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटियों को ताकतवर बनाना होगा।

संभावना यह है कि ये सब बातें जुबानी कवायद तक सीमित रहेंगी, क्योंकि नेतृत्व की रूचि केवल उन लोगों की बातें सुनने में रहती है, जो नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आलोचना और बेबाकी स्वागत और सम्मान योग्य नहीं मानी जातीं।

जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर पर सरकार की मुहर

नई दिल्ली, 28 मार्च। कैश मामले में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आदेश जारी किया गया है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया गया है कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक काम न सौंपा जाए। इधर, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा मामले में सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी जांच कर रही है। रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ मिला तो एफआईआर होगी या मामला संसद को भेजा जाएगा। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का वहां की बार एसोसिएशन विरोध कर रही है। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 27 मार्च को सीजेआई संजीव खन्ना और कॉलेजियम के सदस्यों से मिलकर ट्रांसफर पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने शुक्रवार को भारत की न्यायपालिका के लिए सबसे काला दिन बताया। उन्होंने घोषणा की कि वे जस्टिस वर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करेंगे।

- इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने "शुक्रवार" को न्यायपालिका का काला दिन बताया और शपथ ग्रहण के बहिष्कार की घोषणा की।

बिहार चुनाव में महिलाओं को "कैश इन्सैन्टिव" स्कीम ही, भाजपा की रणनीति का स्तम्भ है

महाराष्ट्र, हरियाणा व दिल्ली चुनाव में यह रणनीति सफल रही है। अतः बिहार में भाजपा ने "लाडली लक्ष्मी योजना" प्रस्तावित की है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 मार्च। चुनावाधीन बिहार के लिये भाजपा की प्रचार-योजना को लेकर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। इस पूर्वी राज्य के नवम्बर में होने वाले चुनावों में महिलाओं के लिए नकदी का प्रलोभन पार्टी की शीर्ष पेशकश हो सकती है।

महाराष्ट्र, हरियाणा तथा दिल्ली चुनावों में अपनाई गई सफल तरकीब के अनुरुप, भाजपा ने बिहार के लिये "लड़की लक्ष्मी योजना" के बारे में विचार बनाया है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के वोट पाने के लिये कई उपायों की दिशा में प्रयास शुरु कर दिये हैं, जैसे- पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करना, स्कूल जाने हेतु बालिकाओं के लिए साइकिल- योजना तथा महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए "जीविका दीदी" योजना लागू करना।

नीतीश कुमार ने 2016 में मुख्यतः महिला ग्रुपों की माँग के जवाब में, राज्य में शराबबंदी भी लागू की थी। लेकिन कुमार ने अभी तक सीधे कैश ट्रांसफर की पेशकश नहीं की है। देखना यह है कि कैश ट्रांसफर किये जाने पर भाजपा का फोकस महिला मतदाताओं में कुमार की छवि एवं स्थिति को मजबूत कर पायेगा या नहीं।

इस बहस के बीच कि कैश ट्रांसफर करने की रणनीति असली प्रशासनिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अपनाई जाती है, कैश ट्रांसफर करने का ट्रैंड जोर पकड़ चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले विधानसभा चुनावों में "लाड़ली

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- वैसे बिहार में महिलाओं को वोट बैंक बनाने की सोच नीतीश कुमार की थी।
- नीतीश ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देना शुरु किया था, पंचायतों में, फिर, स्कूल की छात्राओं को साइकिल की सौगात दी और अंत में 2016 में महिलाओं की मांग पर बिहार में नशाबंदी लागू की। पर, नीतीश ने भी महिलाओं को सीधे "कैश इन्सैन्टिव" देने की सोच को नहीं अपनाया था।
- पर, अब सभी राजनीतिक पार्टियाँ भी महिलाओं के वोट बैंक के महत्व को समझने लग गई हैं तथा उस वोट बैंक को पोषित कर रही हैं। हेमन्त सोरेने भी दोबारा सत्ता में आये "मैया सम्मान" कैश इन्सैन्टिव योजना के कारण तथा केजरीवाल ने भी पंजाब में महिलाओं को "कैश सहायता" देने की योजना की घोषणा की, हालांकि, उस वादे की अभी पूर्ति नहीं हुई है।

म्यांमार में भारी भूकंप, 150 की मौत और 732 घायल

भूकंप के झटके भारत, थाइलैंड, बाँग्लादेश व दक्षिण पश्चिम चीन में महसूस किए गए

यांगून, 28 मार्च। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर थाईलैंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक दिखाई दिया। सरकार ने चेतावनी दी कि अगले 24 घंटों में और भी भूकंप आ सकते हैं। म्यांमार में भूकंप में अब तक लगभग 150 लोग मारे गए हैं और 732 घायल हुए हैं। सेना ने कहा है कि मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है।

बैंकॉक में भूकंप के तेज झटके ने काफी नुकसान पहुंचाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि बैंकॉक में एक इमारत के ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़ कर आठ हो गई है। बैंकॉक के उप राज्यपाल तविदा कामोलवेज ने कहा कि एक अन्य व्यक्ति की भी अलग स्थान पर मौत हुई है। ऐसे में यहां मौत का कुल आंकड़ा 9 हो गया है। बचाव दल के अनुसार, निर्माण स्थल पर अभी भी 100 से अधिक लोग लापता हैं।

- 7.7 रिक्टर तीव्रता के इस भूकंप को रैड कैटगरी में रखा गया है। इसमें दस हजार से एक लाख तक मौतें होने की संभावना होती है।
- थाइलैंड में भूकंप से एक इमारत ढह गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई व 100 से ज्यादा लोग लापता हैं।

भारी तबाही के कारण थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइतोंग्तार्न शिनवात्रा ने इमरजेंसी घोषित कर दी है।

अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, इस भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में 10 हजार से 1 लाख मौतें तक हो सकती हैं।

म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण-पश्चिम चीन सहित, 5 देशों में भूकंप का असर देखा गया। यहां के कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। भारत में कोलकाता, इंफाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल में झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव समेत कई हिस्सों में 7.3 तीव्रता के झटके आए। म्यांमार में 12 मिनट बाद फिर 6.4 तीव्रता का आफ्टरशॉक आया।

म्यांमार में धरती की सतह के नीचे की चट्टानों में मौजूद एक बहुत बड़ी दरार है, जो देश के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। यह दरार म्यांमार के सागाइंग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्रीय कर्मचारियों का 2 प्रतिशत डीए बढ़ा

नई दिल्ली, 28 मार्च। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। इससे लगभग 48.66 लाख सरकारी कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।

- पैन्शनरों को भी मंहगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि दी गई।

सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर साल 6614.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी दरों में साल में दो बार बदलाव होता है। एक बदलाव आमतौर पर मार्च में होता है और दूसरा दिवाली से पहले अक्टूबर में होता है।

पिछले साल अक्टूबर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बेसिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीकानेर सैंट्रल जेल से मु.मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली

14 महीने में चौथी बार मुख्यमंत्री भजनलाल को धमकी दी गई है

बीकानेर, 28 मार्च (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला बीकानेर सेंट्रल जेल का बंदी है। उससे मोबाइल फोन बरामद हुआ है। चौदह महीने में यह चौथी बार है, जब सीएम को धमकी दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी आदिल ने शुक्रवार सुबह 7:30 बजे बीकानेर पुलिस कंट्रोल रूम को मोबाइल से कॉल किया और सीएम को जान से मारने की बात कही। सुबह 8:40 बजे आदिल को गिरफ्तार कर लिया। आदिल ने कॉल क्यों किया और उसके पास मोबाइल कैसे पहुंचा, इसकी छानबीन की जा रही है। जांच में पता चला है कि आदिल नशे का आदी है। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वह पहले भी अपने हाथों की नसें काट चुका है।

- जाँच में पता चला कि बीकानेर सैंट्रल जेल से बंदी आदिल ने यह कॉल किया था, पुलिस ने उससे मोबाइल बरामद किया है।

सूत्रों के अनुसार, आरोपी को बीकानेर सैंट्रल जेल में नशीला पदार्थ नहीं मिल रहा था, इसलिए वह दूसरी जेल में शिफ्ट होना चाहता था। इसी वजह से उसने ये धमकी भरा कॉल किया। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि जेल पुलिस ने अपने स्तर पर ही सर्च अभियान चलाकर आदिल को गिरफ्तार किया है।

इससे पहले, 21 फरवरी की रात को सीएम भजनलाल को दौसा जेल से जान से मारने की धमकी मिली थी। पॉक्सो मामले में जेल में बंद आरोपी ने श्यालवास स्थित सैंट्रल जेल से पुलिस कंट्रोल रुम को 12 बजकर 45 मिनट से लेकर 12 बजकर 55 मिनट के बीच 10 मिनट में दो कॉल किए थे। श्यालवास जेल से 27 जुलाई 2024 को भी जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने जेल में सर्च अभियान चलाकर मोबाइल जब्त किए थे। धमकी देने वाले कैदी के खिलाफ पापड़दा थाने में मामला दर्ज किया गया था। साथ ही, जेल में सिम पहुंचने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, जनवरी 2024 में जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद पॉक्सो एक्ट के बंदी ने ही कंट्रोल रूम में कॉल कर सीएम को गोली मारने की धमकी दी थी।

इसके बाद कॉल काटकर मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। पुलिस टीम ने तकनीकी आधार पर जांच शुरू करके धमकी देने वाले आरोपी की पहचान की थी। इस दौरान जेल में बंदियों से मोबाइल भी जब्त किए गए थे।

ज्ञातव्य है कि गत 26 मार्च को डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी मिली थी। बदमाश ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया था। जिस नंबर से फोन आया, उस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई। मोबाइल की लोकेशन जयपुर सेंट्रल जेल आई। ड्यूटी ऑफिसर ने धमकी भरा फोन आने की सूचना सीनियर्स को दी।